THE DEPUTY CHAIRMAN: Very good. Very sporting Minister!

श्रीमती सविता शारदा (गुजरात): सरला माहेश्वरी जी ने महान् साहित्यकार के विषय में जो कुछ कहा मैं अपने आपको उससे संबद्ध करना चाहती हूं।

उपसभापति : अब तो संजय जी को इजाजत दे दीजिए। वे कितनी सहनशीलता का प्रदर्शन कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं, गुस्सा नहीं कर रहे हैं, कितने अच्छे हो गए हैं इसलिए उन्हें मुबारकबाद दे दीजिए।

श्री संजय निरुपम : महोदया, क्योंकि विषय इस देश के बहुत बड़े साहित्यकार से जुड़ा हुआ है तथा मैंने भी प्रेमचंद को बहुत पढ़ा है और मेरे मन में उनके प्रति बहुत सम्मान है इसलिए मैं चुपचाप बैठा हूं।

उपसभापति : ये भी लेखक हैं, संपादक हैं, बोलिए।

Threat to the Federal Structure of the country by the Maharashtra Government

श्री संजय निरुपम (महाराष्ट्र) : उपसभापति महोदया, महाराष्ट्र सरकार ने पिछले दिनों भारत के संघीय ढांचे को चोट पहुंचाने का एक अक्षम्य अपराध किया। मुंबई में शिवसेना प्रमुख की गिरफ्तारी की किसी भी संभावित प्रतिक्रिया से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बेशुमार सुरक्षा बल तैनात किए। उसके बाद महाराष्ट्र के दो गृह राज्य मंत्रियों ने केंद्रीय गृह मंत्री से अतिरिक्त सुरक्षा बल मांगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने मना कर दिया और कहा कि महाराष्ट्र सरकार को अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। इसकी प्रतिक्रिया में महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने यह घोषणा की कि अगर केंद्र हमें अतिरिक्त सुरक्षा बल नहीं देगा तो हम मुंबई में केंद्र सरकार के जितने भी संस्थान हैं उन संस्थानों की सुरक्षा के लिए तैनात राज्य सरकार के पुलिस बलों को हटा लेंगे। यह भारत के संघीय ढांचे को चुनौती देने वाला वक्तव्य है - महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने न सिर्फ यह वक्तव्य दिया बल्कि मुंबई के एअर पोर्ट की सुरक्षा के लिए तैनात राज्य सरकार की पुलिस को वापस ले लिया। मुंबई में केंद्र सरकार के कई संवेदनशील संस्थान हैं। मसलन, आणविक ऊर्जा केंद्र। ऐसे संस्थानों की सुरक्षा राष्ट्रीय महत्व का विषय है। इसकी जिम्मेदारी केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार की भी है। अगर राष्ट्रीय महत्व के संवेदनशील संस्थानों की सुरक्षा देने की जिम्मेदारी से राज्य सरकारें पीछे हटने लगीं तो केंद्र के पास क्या विकल्प रहेगा? ऐसी स्थिति में भारत का संघीय ढांचा कितना सुरक्षित रहेगा? क्या मुंबई के एअरपोर्ट से राज्य सरकार द्वारा राज्य की पुलिस हटाने का निर्णय केंद्र के ध्यान में आया है? क्या इस अपराध के लिए केंद्र ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई की है? क्या यह सच है कि 25 जुलाई, 2000 को शिव सेना प्रमुख की गिरफ्तारी के समय मुंबई पुलिस के निर्देश पर एमटीएनएल ने लगभग तीन घंटे तक सारे फोन बंद कर दिए थे? क्या केंद्र सरकार के अधिकारियों पर किसी राज्य की पुलिस को अपना हुक्म चलाने का अधिकार है? क्या केंद्र सरकार इस पूरे मामले की जांच कराना चाहेगी? धन्यवाद।

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश): साथ में जो हाई कोर्ट का आब्जर्वेशन है उसको जांच की परिधि में ले आइए। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय निरुपम : वकील साहब आकर ---

उपसभापति : इसकी मैंने इजाजत नहीं दी है।

श्री संजय निरुपम : हाई कोर्ट में आपने अपील की थी ...(व्यवधान)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: No discussion Sanjayji, Shri Dhamma Viriyo

SHRI PRAFUL PATEL (Maharashtra): Madam, if you are permitting Mr. Sanjay Nirupam to speak, I will also speak.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Nobody will speak.

Appointment of Director of Nava Nalanda Mahavihar

VEN'BLE DHAMMAVIRIYO (Bihar): Madam, the Ministry of Culture has recently appointed a Director in the Nava Nalanda Mahavihar, an internationally reputed institute, grossly violating the minimum dignity and convention of the universities, particularly a university of the stature of the Nalanda University. The appointed person is a simple M.A. Ph.D. and is working as a proof reader in the Vipasana Vidyapeeth, Nasik, Maharashtra. The appointment will destroy the institution since he is only 42 years old and is supposed to continue as Director for minimum 20 years. This is an affront to the glorious heritage, fame and tradition that the institute is enjoying since ancient times. Moreover, the appointment is not acceptable to the academic community, particularly the Buddhist world. The renowned personalities like Dr. Prof. Jagdish Kashyap, Prof. Satkari Mukherjee, Prof. Rath, Dr. Dipak Barua, Prof. Chandrika Prasad, worked as Directors in this institution, and produced more than two hundred Buddhist scholars. Some of them who are working as professors, Vice-Chancellors and diplomats are shocked to see the appointment. It is also surprising that the recommendations of the experts of the Selection Committee were ignored. In view of the above reasons, we request the Ministry of Culture to cancel the appointment of Director, Nava Nalanda Mahavihar. Thank you.

SHRI EDUARDO FALEIRO (Goa): Madam, I would like to associate myself with this Special Mention because this is one of many appointments which are made without any regard to the academic merit, on political and partisan considerations, to control organisations ...*(Interruptions)*...

SHRI T.N. CHATURVEDI (Uttar Pradesh): Madam, if this is the association, ...*(Interruptions)*...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU (Karnataka): Madam, what is he speaking? Have you relaxed the rules? ...*(Interruptions)*... It is his experience, but our experience is different.